दिनांक–03 सितम्बर 2025 **7:20 AM**

पहले मुख्य समाचार।

- प्रदेश कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड के गठन सहित पंद्रह प्रस्तावों को मिली मंजूरी। अब निगम द्वारा ही जेम पोर्टल के जरिए चयनित की जाएंगी आउटसोर्सिंग एजेंसियां।
- लखनऊ और कानपुर सहित आसपास के कस्बों के लिए सौ–सौ ई–बसों को खरीदने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट में मिली स्वीकृति। नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर होगा इन बसों का संचालन।
- सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में प्राथमिक और जूनियर कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया। तय समयसीमा में टीईटी पास न करने पर शिक्षकों को छोड़नी पड़ेगी नौकरी।
- नेपाल तथा भूटान के नागरिकों को पहले की तरह पासपोर्ट या वीजा प्रस्तुत करने की आवश्यकता समाप्त।

****

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल लखनऊ के लोकभवन में हुई कैबिनेट की बैठक में पंद्रह प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई । बैठक के बाद आयोजित प्रेसवार्ता में प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड के गठन को अपनी मंजूरी दे दी। इसके माध्यम से अब आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन सीधे विभाग नहीं करेंगे। निगम द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से एजेंसियों का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट–

आउटसोर्स कर्मचारियों का चयन तीन वर्षों के लिए किया जाएगा। कर्मचारियों के लिए कम से कम सोलह से बीस हजार रुपये का मानदेय निर्धारित किया गया है। आउटसोर्स कर्मचारियों से महीने में छब्बीस दिन सेवा ली जा सकेगी। उनका वेतन एक से पांच तारीख तक उनके खाते में आ जाएगा। ईपीएफ और ईएसआई का अंशदान अब सीधे कर्मचारियों के खाते में जाएगा। समाचार कक्ष से प्रेम चन्द्र गुप्ता।

वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था की अनियमितताओं को खत्म करने और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए ही निगम का गठन किया गया है।

उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की वह कम्पनीज एक्ट दो हजार तेरह के सेक्शनआठ के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल का जो गठन किया गया है। उसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कारगरों की सेवाएं दी जा रही है उसको बेहतर बनाने के लिए मंत्रिपरिषद के समक्ष एक प्रस्ताव आया। इसमें विशेष बात यह है कि नियमित पदों के अगेंस्ट इसमें आउटसोर्स या संविदा पर नहीं दिए जाएंगे।

लखनऊ और कानपुर सहित आसपास के कस्बों के लिये सौ–सौ ई–बसें खरीदने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी । इसके तहत नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर ई–बसों का संचालन किया जायेगा। प्रेसवार्ता में नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा और बेहतर होगी।

परिवहन सुविधा को बेहतर बनाने के लिए प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा था कि नेटकास्ट बेसिस पर प्राइवेट ऑपरेटर को हम लोग लाइसेंस दें और वो लोग अपने घाटा मुनाफा के बदौलत सरकार उनको कोई पैसा नहीं देगी। सिर्फ उनको एक वैधानिक सपोर्ट देते हुए ई–चार्जिंग वगैरह की जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुविधा देते हुए सारा का सारा खर्च प्राइवेट ऑपरेटर उठावे इस स्तर पर नेट कास्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मॉडल बोलते हैं उसको उसमें प्रयोग के रूप में कानपुर और लखनऊ के दस दस रूट पर सुविधा करने का मंशा है और उसे माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिये हैं।

कैबिनेट की बैठक में निर्यात प्रोत्साहन नीति दो हजार पचीस–तीस को भी मंजूरी मिल गई। नई नीति में दो हजार बीस–पचीस की निर्यात नीति में सुधार करते हुए डिजिटल तकनीकी अवसंरचना, विकास, वित्तीय सहायता, निर्यात ऋण और बीमा, बाजार विस्तार, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण पर विशेष बल दिया गया है।

कैबिनेट ने पैतृक सम्पत्ति के बंटवारे के लिये रजिस्ट्री शुल्क पांच हजार रुपये किये जाने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया। बैठक के दौरान शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल गई।

****

विकसित उत्तर प्रदेश के लिये तैयार हो रहे विजन डॉक्यूमेंट के लिये अब जनता से विभिन्न मुद्दों पर राय ली जायेगी। इसके लिये एक विशेष पोर्टल और क्यूआर कोड तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पोर्टल की लॉचिंग करेंगे। नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि गांव और शहरों में यह क्यूआर कोड लगाये जा रहे हैं।

****

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में प्राथमिक और जूनियर कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिये टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया है। शिक्षकों को इसे दो वर्ष में उत्तीर्ण करना होगा। तय समय सीमा में टीईटी पास न करने वाले शिक्षकों को नौकरी छोड़नी होगी, हालांकि सेवानिवृत्ति के सभी लाभ उन्हें मिलेंगे। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट–

शीर्ष अदालत का यह फैसला देशभर के प्राथमिक और जूनियर कक्षाओं के शिक्षकों पर सामान्य रूप से लागू होगा। यह फैसला उन शिक्षकों पर भी लागू होगा, जिनकी नियुक्ति शिक्षा के अधिकार–आरटीई कानून लागू होने से पहले हुई थी। जस्टिस दीपांकर

दत्ता और जस्टिट मनमोहन की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से कम बची है, उन्हें टीईटी उत्तीर्ण किये बगैर सेवानिवृत्ति तक सेवा में बने रहने की अनुमति है, लेकिन उन्हें पदोन्नति नहीं मिलेगी। यदि वे पदोन्नति चाहते हैं, तो उन्हें भी टीईटी पास करना होगा। पीठ ने अंजुमन–इशात–ए तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र सरकार सहित कई अन्य की अपीलों पर यह फैसला सुनाया है। समाचार कक्ष से सुषमा कुकरेती।

****

गृह मंत्रालय ने नेपाल और भूटान के नागरिकों को जमीनी या हवाई मार्ग से भारत में प्रवेश करने के लिए पहले की तरह पासपोर्ट या वीजा प्रस्तुत करने की आवश्यकता समाप्त कर दी है। इसके लिए मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी नागरिकों को छूट आदेश, दो हजार पचीस अधिसूचित किया है।

****

प्रदेश सरकार ने नवगठित मुरादाबाद के गुरु जम्भेश्वर विश्विद्यालय, मिर्जापुर के मां विन्ध्यवासिनी विश्वविद्यालय और बलरामपुर के मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय में कुल नौ सौ अड़तालीस नये पदों के सृजन को मंजूरी दे दी। इनमें 468 अस्थाई शिक्षणेत्तर पद और 480 आउटसोर्सिंग पद भी शामिल हैं। उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने कहा कि इन पदों के सृजन से विश्वविद्यालयों की प्रशासनिक और कार्यात्मक व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी । साथ ही शैक्षिक गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी।

****

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हो रही लगातार बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियां उफान पर हैं। यमुना के बढ़ते जलस्तर की वजह से मथुरा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गौतमबुद्धनगर में भी यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे वहां बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। जिले के सदर तहसीलदार प्रतीक चौहान ने बताया कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है।

यहाँ बाल शरणालय बने हुए हमारे, वहाँ पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोग स्वेच्छा से पुछ्ते पर भी अपना अस्थायी निवास बना लिए है जिनके खान पान की व्यवस्था की गयी है और कम्युनिटी किचन भी यहाँ पे चालू कर रहे हैं।

बागपत में भी यमुना में हथिनीकुंड बैराज से 3.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने की वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं। सहारनपुर में भारी बारिश के कारण हेमकुंड एक्सप्रेस और शालीमार–मैलानी एक्सप्रेस को 30 सितंबर तक रद्द किया गया है। फर्रुखाबाद, पीलीभीत, मथुरा और हापुड़ में कक्षा एक से बारहवीं तक के विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। बलिया, प्रयागराज, वाराणसी और बदायूं सहित सत्रह जिलों की ढाई लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है।

****

राज्य स्तरीय कोबुडो मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में लखनऊ की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया है। प्रतियोगिता में कानपुर नगर विजेता और चंदौली उपविजेता रहा, लखनऊ ने 4 स्वर्ण, 5 रजत और एक कांस्य पदक सहित कुल दस पदकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है।

****